सुरिंदरजीत सिंह मंड और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 565/2016)

जुलाई 05, 2016

[जगदीश सिंह खेहर और सी. नागप्पन, जे.जे

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 197- अभियोजन से पहले मंजूरी- 28.6.1999 को पुलिस अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी- गिरफ़्तार व्यक्ति की माँ द्वारा अपने बेटे को 24.6.1999 से 28.6.1999 तक अवैध और अनधिकृत हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए शिकायत- धारा 197 के तहत मंजूरी प्राप्त करने के बाद छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन- अपीलार्थी-पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए धारा 319 के तहत शिकायतकर्ता का आवेदन- अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए- पुनरीक्षण में इस आधार पर चुनौती दी गई कि अभियोजन की मंजूरी के अभाव में अपीलकर्ताओं पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था -उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण ख़ारिज- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया कि: धारा 197 को लागू करने के लिए, यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या कथित अपराध "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का इरादा रखते हुए" किया गया था- वर्तमान मामले में, 28.6.1999 से गिरफ्तारी की अवधि (जब गिरफ्तारी स्वीकार की गई थी) को "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य

करते समय या कार्य करने का आशय रखते हुए"," माना जा सकता है, लेकिन 24.6.1999 से 28.6.1999 तक अवधि नहीं मानी जा सकती है। इसलिए, अपीलकर्ता-अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

धारा 197, 319- धारा 197 का दायरा- क्या धारा 197 का अधिदेश उन मामलों तक विस्तारित होगा जहां धारा 319 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लिया गया है? अभिनिर्धारित किया कि- सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से पहले, धारा 197 के तहत स्वीकृति का आदेश एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है, भले ही धारा 319 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लिया गया हो।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कथित कार्रवाई 24.06.1999 से 28.06.1999 तक 'एन' की गिरफ्तारी और हिरासत पर आधारित है (इससे पहले, उसे 28.06.1999 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था)। जहां तक पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत की शक्ति का सवाल है, सीआरपीसी की धारा 36, 49, 50 और 50ए का संदर्भ दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 36 के मद्देनजर, इस तथ्य के बारे में कोई गंभीर संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता प्रासंगिक समय पर (24.06.199 से 28.06.1999 तक) पुलिस उपाधीक्षक के पद पर थे। दोनों अपीलकर्ता "... अधिकारी थे, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ थे..."। इसलिए दोनों अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक समय पर (24.06.1999 से 28.06.1999 तक) 'एन' को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त था। धारा 49, 50 और 50ए में आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रश्न संदर्भाधीन अवधि (24.06.1999 से 28.06.1999 तक) के लिए नहीं उठता, क्योंकि

आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 'एन' को 28.06.1999 को ही गिरफ्तार किया गया था। [पैरा 12, 13 और 14)(670-जीएच; 671-ए-डी, एफ]

1.2 जब वर्तमान प्रकृति की प्रतिपादना का सामना किया जाता है, तो यह पता लगाना होता है कि क्या कथित अपराध, जिसके लिए अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया जाता है, एक अभियुक्त द्वारा "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के उद्देश्य से" किया गया था। सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार 'एन' की आधिकारिक गिरफ्तारी 28.06.1999 से 30.06.1999 की अवधि के दौरान बढ़ेगी। हिरासत की उपरोक्त अवधि को वैध रूप से "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के उद्देश्य से" के रूप में माना जा सकता है। अपीलकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई तथ्यात्मक स्थिति यह है कि 'एन' को 24.06.1999 से 28.06.1999 तक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं लिया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान उनकी हिरासत, यदि सच है, तो निश्चित रूप से अभियुक्तों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कार्य करने या कार्य करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई से सामने नहीं आएगी। यदि यह विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सबूतों से प्रकट होता है कि 'एन' को वास्तव में 24.06.1999 से 28.06.1999 तक की अवधि के दौरान हिरासत में लिया गया था, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त हिरासत अभियुक्तों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कार्य करते समय या कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। इससे भी अधिक, क्योंकि यह अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है, कि उन्होंने 24.06.1999 से 28.06.1999 की अवधि के दौरान 'एन' को जेल में रखा था। [पैरा 12 और 17[670-एफ; 673-ई-एच; 674-ए]

1.3 इसलिए, 24.06.1999 से 28.06.1999 तक की अवधि के लिए 'एन' की हिरासत के संबंध में अभियुक्त के अभियोजन के लिए, सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष जो की 'एन' की कथित गिरफ्तारी के संदर्भ में संज्ञान लेता है, मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी. [पैरा 17](674-बी-सी)]

पी.पी. उन्नीकृष्णन बनाम पुट्टियोट्टिल अलीकुट्टी (2000) 8 एससीसी 131 : 2000 (3) पूरक। एससीआर 142- पर भरोसा किया।

डॉ. होरी राम सिंह बनाम एम्परर एआईआर (1939) एफसी 43; शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास (2006) 4 एससीसी 584: 2006 (3) एससीआर 305; आर बालाक्रिसल्मा पिल्लई बनाम केरल राज्य (1996) 1 एससीसी 478 :1995 (6) पूरक। एससीआर 236; पी.के. प्रधान बनाम सिक्किम राज्य (2001) 6 एससीसी 704 : 2001 (3) एससीआर 1119; ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य (2012) 12 एससीसी 72 : 2012 (9) एससीआर 125; उषारानी बनाम पुलिस आयुक्त (2015) 2 सीआरएलजे 511 का सन्दर्भ दिया गया,

2. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत और/या एक विशेष क़ानून के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष जो किसी अपराध का संज्ञान लेता है (चाहे भारतीय दंड संहिता के तहत, या संबंधित विशेष वैधानिक अधिनियमन के तहत)। अनिवार्य मंजूरी (जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्धारित है) एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता होगी. मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया सीआरपीसी के प्रावधानों और/या विशेष अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से नियंत्रित होगी। सीआरपीसी की धारा 197 में शब्द हैं, "...कोई भी अदालत पूर्व मंजूरी के बिना

ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी..."। इसी तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रावधान है, "कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा.. सिवाय पिछली मंजूरी के "। आदेश स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय बिना मंजूरी के संज्ञान नहीं लेगा। इसलिए, कोई भी न्यायालय बिना उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के संज्ञान नहीं ले सकता. इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां सीआरपीसी की धारा 319 के तहत संज्ञान लिया गया है, वहां सीआरपीसी की धारा 197 (या संबंधित विशेष अधिनियम के तहत) के तहत मंजूरी अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय द्वारा किया गया निर्धारण , धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अधीन है। धारा 197 के तहत मंजूरी को अभियुक्त द्वारा न्यायिक समीक्षा का सहारा लेकर चुनौती दी जा सकती है। इसी तरह, मंजूरी को अस्वीकृत करने के आदेश को भी शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष द्वारा चुनौती दी जा सकती है। [पैरा 22 और 23)(681-ई-एच; 682-बी-सी)]

दिलावर सिंह बनाम परविंदर सिंह उर्फ इकबाल सिंह (2005) 12 एससीसी 709: 2005 (5) पूरक, एससीआर 83; पॉल वर्गीस बनाम केरल राज्य (2007) 14 एससीसी 783: 2007 (4) एससीआर 1155; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) 3 एससीसी 64: 2012 (3) एससीआर 52- पर भरोसा किया।

वाद सन्दर्भ

एआईआर_ (1939) एफसी 43- संदर्भित- पैरा 10

2006 (3) एससीआर 305- संदर्भित- पैरा 10

1995 (6) पूरक। एससीआर 236- संदर्भित- पैरा 10

2001 (3) एससीआर 1119- संदर्भित- पैरा 10

2912 (9) एससीआर 125- संदर्भित- पैरा 11

(2015) 2 कार्ल 511- संदर्भित- पैरा 11

2000 (3) पूरक एससीआर 142- पर भरोसा- पैरा 16

2005 (5) पूरक एससीआर 83- पर भरोसा- पैरा 21

2007 (4) एससीआर 1155- पर भरोसा- पैरा 21

2012 (3) एससीआर 52- पर भरोसा- पैरा 21

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 565/2016

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 09/01/2008 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 348/2007 में पारित निर्णय और आदेश से

अपीलकर्ताओं के लिए राम जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, चिराग मदान, अनिरुद्ध आनंद, अजय अवस्थी, अनुभव, पी.आर. माला, यशपाल ढींगरा, अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए जयंत के. सूद, एएजी, सुश्री जसलीन चहल, सहायक एजी, वरिंदर सिंह राणा, जीवन गौतम (सुभाशीष भौमिक के लिए) हनी खन्ना, अजय पी. तुशीर (कुलदीप सिंह के लिए).

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. सुरिंदरजीत सिंह मंड और पी.एस.परमार इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता, पुलिस उपाधीक्षक के पद पर रहते हुए, प्रासंगिक अवधि 1999 में, पंजाब राज्य के जिला कपूरथला में तैनात थे। प्यारा लाल (सहायक उप-निरीक्षक का पद पर) भी उसी समय कपूरथला में तैनात थे।उपर्युक्त प्यारा लाल के बेटे-नीरज कुमार को आधिकारिक तौर पर 28.06.1999 पर गिरफ्तार किया गया था।नीरज कुमार की गिरफ्तारी, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30 के अनुसरण मे की गई थी, जिसे 03.03.1999 पर पुलिस स्टेशन सिटी, कपूरथला में दर्ज किया गया था।नीरज कुमार की गिरफ्तारी से पहले, उनके पिता प्यारा लाल को 10.06.1999 को निलंबित कर दिया गया था।हमे बताया गया कि उपरोक्त प्राथमिकी संख्या 30 कपूरथला के निवासियों द्वारा शहर में मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों की चोरी से संबंधित शिकायतों के संबंध में थी।

3. यह बताया गया कि 03.03.1999 की शिकायत में निहित आरोपों की जांच करते हुए, नीरज कुमार सहित तीन व्यक्तियों को 28.06.1999 पर गिरफ्तार किया गया था। नीरज कुमार को 30.06.1999 पर जमानत दी गई थी। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि नीरज कुमार लगभग दो/तीन दिनों (28.06.1999 से 30.06.1999 तक) के लिए जेल में रहे थे। नीरज कुमार (प्राथमिकी संख्या 30 की जाँच के दौरान हिरासत में लिए गए) की माँ उषा रानी ने एक अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उनके बेटे को 24.06.1999 पर हिरासत में लिया गया था (न कि 28.06.1999 पर, जैसा कि कहा गया है)। इससे उसकी गिरफ्तारी की अवधि छह/सात दिन हो जाएगी।वर्तमान विवाद नीरज कुमार की गिरफ्तारी के अतिरिक्त चार/पांच दिनों से संबंधित है।उनकी शिकायत ने इस बात पर ज़ोर डाला कि उनके

बेटे-नीरज कुमार को अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से 24.06.1999 से 28.06.1999 यानी चार/पाँच दिनों के लिए हिरासत मे रखा गया था।

4. उषा रानी द्वारा की गई शिकायत की जांच सबसे पहले आई. पी. एस. मुनीश चावला द्वारा करने का निर्देश दिया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि नीरज कुमार की मां द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकी। फिर भी, उषा रानी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, एक और जांच का आदेश दिया गया।इस बार, इसका एम. एफ. फारूकी, आई. पी. एस. द्वारा किया गया। फिर भी, दूसरी जाँच में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि नीरज कुमार 24.06.1999 से 28.06.1999 तक, उसकी औपचारिक गिरफ्तारी तक पुलिस हिरासत में थे।दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों के बावजूद, जिसमें यह पाया गया था कि उषा रानी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं था, आई. पी. एस. गुरप्रीत देव ने अपने दम पर मामले की जांच की। वह भी उसी निष्कर्ष पर पहुंची, कि उषा रानी के दावे में कोई दम नहीं था, कि उनके बेटे को 28.06.1999 पर औपचारिक गिरफ्तारी से पहले पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से हिरासत में लिया गया था।

5॰ इस बार 01.10.1999 को, उषा रानी (नीरज कुमार की माँ) ने एक और लिखित शिकायत माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश) को की, जिनके पास सत्र प्रभाग, कपूरथला का प्रभार है, अपनी शिकायत में, उन्होंने दोहराया कि उनके बेटे नीरज कुमार को 24.06.1999 पर पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश ने कपूरथला के सत्र प्रभाग में तैनात एक अतिरिक्त

जिला और सत्र न्यायाधीश को दिनांक 01.10.1999 की शिकायत को भेजा, जिसमें उन्हें मामले को देखने के लिए कहा। संबंधित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, कपूरथला ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि नीरज कुमार को गलत तरीके से फंसाया गया था, क्योंकि उन्हें और कुछ अन्य अभियुक्तों को अदालत ने उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही से मुक्त कर दिया था। उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 25.09.2000 के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46, 22.10.2002 को पुलिस स्टेशन सिटी कपूरथला में दर्ज की गई।

6. उपरोक्त प्राथमिकी संख्या 46 में पुलिस अनुसंधान पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपूरथला की अदालत में 25.05.2003 को छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। उपरोक्त आरोप पत्र दायर किए जाने से पहले, अभियोजन पक्ष ने छह संबंधित पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत मंजूरी प्राप्त की थी। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यह अपीलार्थियों का स्पष्ट तर्क था कि जांच के समापन पर, अपीलार्थियों की कोई भागीदारी सामने नहीं आई थी, और इसलिए, उनके नाम कॉलम संख्या 2 में दर्ज किए गए थे। यह तर्क दिया गया कि कॉलम संख्या 2 में अपीलार्थियों के नामों का उपरोक्त चित्रण उनकी बेगुनाही को दर्शाता है (उषा रानी द्वारा लगाए गए आरोपों के संदर्भ में, कि उनके बेटे नीरज कुमार को अवैध रूप से 24.06.1999 से हिरासत में लिया गया था)।

7. यह विवाद का विषय नहीं है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद, उषा रानी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए विचारण न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कपूरथला के समक्ष 'संहिता' की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया।उपरोक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने 06.09.2003 पर अनुमति दी थी इसके बाद, अपीलार्थियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपूरथला द्वारा मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। अपीलकर्ताओं ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने समन का विरोध करते हुए कहा कि उनका अभियोजन कानूनी रूप से असंधार्य था, क्योंकि उनके खिलाफ संज्ञान लेने से पहले 'संहिता' की धारा 197 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

8. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को तलब किए जाने के परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ 23.12.2006 पर आरोप तय किए गए थे।विचारण न्यायालय द्वारा 23.12.2006 को अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को अपीलार्थियों द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 348/2007 द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से प्राथमिक निवेदन यह था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपूरथला, 'संहिता' की धारा 197 के तहत अभियोजन की मंजूरी की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 09.01.2008 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। उपरोक्त दिनांकित 09.01.2008 आदेश इस अपील द्वारा से चुनौती का विषय है।

9. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री राम जेठमलानी ने अपीलार्थियों के दावे के समर्थन के क्रम मे 'संहिता' की धारा 197 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसे यहां निकाला गया हैः

“197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन।

(1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था, जिसे सरकार द्वारा या उसकी अनुमति के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है, उस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जो उसके द्वारा कार्य करते समय या कार्य करने के लिए कथित तौर पर किया गया है। अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा (जैसा कि लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 में अन्यथा प्रावधान किया गया है)

(ए) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित है या कथित अपराध के समय नियोजित था;

(बी) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो, जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के मामलों के संबंध में, राज्य सरकार के नियोजित अपराध के समय नियोजित है या था:

बशर्ते कि जहां कथित अपराध उस अवधि के दौरान खंड (बी) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा एक राज्य में लागू थी, खंड (बी) इस प्रकार लागू होगा जैसे कि उसमें आने वाली अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" के स्थान पर "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की गई।

(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति का निर्धारण कर सकती है जिसके द्वारा, किस तरीके से, और उस अपराध या अपराध के लिए, जिसके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक पर

अभियोजन चलाया जाना है, और उस न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष मुकदमा चलाया जाना है।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात पर प्रकाश डाला कि 'संहिता' की धारा 197 के तहत मंजूरी अनिवार्य है, जहां संबंधित लोक सेवक पर "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए" अपराध करने का आरोप लगाया जाता है।

10. "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का इरादा रखते हुए" शब्द के दायरे और दायरे को प्रदर्शित करने के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने डॉ. होरी राम सिंह बनाम पर भरोसा जताया जिसमे एम्परर, एआईआर (1939) एफसी 43, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> “लेकिन स्पष्ट शब्दों में धारा 477-A एक अधिकारी के मामले को शामिल करता है, जो जानबूझकर विवरणों को गलत बताता है जिसे बनाए रखना उसका कर्तव्य हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चोरी, गबन या विश्वासघात को विवरणों के मिथ्या प्रदर्शन के समान ही रखा है, और विवरणों को गलत साबित करने के आरोप को आपराधिक न्यास भंग से अलग नहीं माना है। यह उन शब्दों के महत्व को नजरअंदाज कर रहा है जो "किए जाने के आशय" जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।उन्होंने सोचा है कि राजा के सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में किया गया या किया जाने वाला कोई कार्य अंग्रेजी भाषा के किसी भी विस्तार से किसी ऐसे कार्य पर लागू नहीं किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से उसके कर्तव्य की अवहेलना है।लेकिन यदि कोई कार्य कर्तव्य के निष्पादन में किया जाना अपेक्षित है, तो ऐसा किया जा सकता है, केवल जाहिरा तौर पर और वास्तव में नहीं, और यदि बेईमानी से किया जाता

है तो भी कर्तव्य की अवहेलना हो सकती है।उच्च न्यायालय की पीठ ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह धारा स्पष्ट रूप से एक लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य पर लागू होती है जिसे सद्भावना से किया जा सकता है, लेकिन जो संभवतः बदनीयत में भी किया जा सकता है, धारा उन मामलों में लागू नहीं हो सकती है जहां इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कथित कृत्य बुरे विश्वास से किया गया होगा। जहाँ तक उप-धारा (1) का संबंध है, अच्छे विश्वास या बुरे विश्वास का प्रश्न सख्ती से नहीं उठ सकता है, क्योंकि उपयोग किए गए शब्द न केवल "अपने कर्तव्य के निष्पादन में किया गया कोई कार्य" हैं, बल्कि "अपने कर्तव्य के निष्पादन में किया जाने वाला कोई कार्य" भी हैं। जब कोई कार्य उसके कर्तव्य के निष्पादन में नहीं किया जाता है, बल्कि उसके कर्तव्य के निष्पादन में किया जाता है, तो यह बहुत अच्छी तरह से बुरे विश्वास में किया जा सकता है; और यहां तक कि एक कार्य जो कर्तव्य के निष्पादन में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है यदि दूसरे को गलत तरीके से विश्वास दिलाया जाता है कि वह कर्तव्य के निष्पादन में किया जा रहा था। इसलिए धारा की प्रयोज्यता को केवल ऐसे मामलों तक सीमित करना संभव नहीं है जहां कोई कार्य संभवतः अच्छे और बुरे विश्वास दोनों में किया जा सकता था।निःसंदेह, अच्छे या बुरे विश्वास के प्रश्न पर प्रारंभिक चरण में विचार नहीं किया जा सकता, जिस पर आपत्ति की जा सकती है।रजिस्टर में गलत प्रविष्टियाँ करना कर्तव्य के निष्पादन में किया जाना एक कार्य हो सकता है, जो एक अपराध होगा, हालाँकि इसे कभी भी सद्भावना से नहीं किया जा सकता है।यह केवल उपधारा 2 है जो सद्भावना के तत्व का परिचय देता है, जो न्यायालय को कार्यवाही को खारिज करने के उसके दायित्व से मुक्त करता है।लेकिन वह उप-धारा उन मामलों से संबंधित है जो पहले भी

संस्थित किए गए थे और जिनमें सहमति की कमी का कोई दोष नहीं हो सकता है, और इसलिए यह काफी अलग है, और न केवल उप-धारा 1 के लिए सहायक है, जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने माना था।"किए जाने का तात्पर्य" शब्दों के सामान्य और प्राकृतिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि इसका अर्थ आवश्यक रूप से "अच्छे विश्वास में किए जाने का तात्पर्य" है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य के निष्पादन में कार्य करता है फिर भी ऐसा कार्य करने का अभिप्राय है, यद्यपि उसका इरादा गलत हो सकता है।"

शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास, (2006) 4 एससीसी 584 पर भी भरोसा किया गया, जिसमें से हमारा ध्यान निम्नलिखित पैराग्राफ की ओर लाया गया :

"25. उच्च न्यायालय ने कहा है कि अत्यधिक बल प्रयोग से किसी व्यक्ति की हत्या करना कभी भी कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता है।यह जहाँ तक जाता है, सही हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह कार्य कर्तव्य के पालन में किया गया था या कर्तव्य के तात्पर्यित पालन में। यदि यह कर्तव्य के पालन या कर्तव्य के तात्पर्यित पालन में किया गया था, तो संहिता की धारा 197 (1) को इस तर्क से दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की हत्या कभी भी आधिकारिक क्षमता में नहीं की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप संहिता की धारा 197 (1) को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। इस तरह का तर्क इस न्यायालय के पहले निर्दिष्ट निर्णयों के अनुपात के खिलाफ होगा। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा तर्क कि यदि उच्च न्यायालय मंजूरी के अभाव के आधार पर हस्तक्षेप करता है, तो लोग न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास खो देंगे, यह भी किसी वैधानिक आवश्यकता या संरक्षण

को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता है। संस्थान में जनता का विश्वास उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कारणों को स्वीकार करके, उसे सौंपे गए कर्तव्यों का कानून और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और बिना किसी देरी के निर्वहन किया जा सकता है।क्षेत्राधिकार संबंधी या वैधानिक आवश्यकताओं से छुटकारा, जो अंततः निर्णय को ही प्रभावित कर सकता है, इसके परिणामस्वरूप लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के तहत मंजूरी की क्षेत्राधिकार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि इस मामले में धारा 197 (1) के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।हम मानते हैं कि इस तरह की मंजूरी आवश्यक थी और मंजूरी के अभाव में अभियोजन को इस स्तर पर खारिज किया जाना चाहिए।शिकायतकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील का जवाब देना अब हमारे लिए नहीं है कि यह इस तरह की मंजूरी देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त मामला है।"

विचारित प्रतिपादना को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य, (1996) 1 एससीसी 478 की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

6. अगला सवाल यह है कि क्या यह कहा जा सकता है की अपीलकर्ता पर अपराध का आरोप लगाया गया है वह उसके अपने कर्तव्य निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते किया है. राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि साजिश के आरोप पर संहिता की धारा 197

लागू नहीं होगी, क्योंकि यह एक मंत्री के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आपराधिक साजिश में शामिल हो। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने हरिहर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1972) 3 एससीसी 89 में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया। उन्होंने हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 74 में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया, जहां न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या जिन कृत्यों की शिकायत की गई थी, वे संबंधित लोक सेवकों के आधिकारिक कर्तव्यों से सीधे संबंधित थे, उन्होंने पाया कि आपराधिक साजिश में शामिल होना एक लोक सेवक का कर्तव्य नहीं था और इसलिए संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी की कमी अभियोजन में कोई बाधा नहीं थी। यह प्रश्न कि क्या शिकायत किए गए कृत्यों का संबंधित लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ सीधा संबंध था, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसी कोई सामान्य प्रतिपादना नहीं हो सकती है कि जब भी किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्यालय में या उसके बाहर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया जाता है तो संहिता की धारा 197 (1) का कोई उपयोग नहीं होगा। ऐसा दृष्टिकोण संहिता की धारा 197(1) को संदिग्ध बना देगा। इसलिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों में प्रश्नों की जांच करनी होगी। न्यायालय द्वारा उस मामले के विशेष तथ्यों में टिप्पणियाँ की गईं, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि तीन अपराधी लोक सेवकों द्वारा की गई आपराधिक साजिश का उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं था और इसलिए, धारा जे 97(1) का निषेध आकर्षित नहीं किया गया. यह भी याद रखना चाहिए कि उक्त निर्णय धारा 197(आई) को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, जैसा कि तब था, लेकिन हम अपना निर्णय उस भेद पर आधारित

नहीं करते हैं।इसके बाद हमारा ध्यान बी साहा बनाम एमएस कोचर, (1979) 4 एससीसी 177 मामले में तीन न्यायाधीशों के फैसले की ओर आकर्षित कराया। जिन प्रासंगिक टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, वे निर्णय के पैराग्राफ 17 में हैं। यह व्यक्त किया गया कि शब्दों "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के प्रयोजन के दौरान उसके द्वारा किया गया कथित कोई अपराध" से संहिता की धारा 197 (1) लगी, जो की संकीर्ण और व्यापक दोनों तरह की व्याख्या करने में सक्षम हैं, लेकिन न्ययाधिपतिगण ने व्यक्त किया की यदि उन्हें बहुत संकीर्ण रूप से समझा गया, तो धारा पूरी तरह से निष्फल हो जाएगी, क्योंकि, "अपराध करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, और कभी नहीं हो सकता है"। साथ ही, यदि उन्हें बहुत व्यापक रूप से समझा जाता है, तो वो, एक अपराध गठित करने वाले प्रत्येक कार्य जो उसी संव्यवहार के दौरान किया जाता है जिसमें आधिकारिक कर्तव्य का पालन किया जाता है या किया जाना कथित होता है, को संरक्षण देंगे। यह बताया गया कि सही दृष्टिकोण यह देखना था कि इस अभिव्यक्ति का अर्थ इन दो चरम सीमाओं के बीच है। जहां एक ओर, एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के पालन के दौरान किया गया हर अपराध संरक्षण का हकदार नहीं है। केवल एक कार्य जो अपराध गठित करता है, प्रत्यक्ष या उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता होगी। संक्षेप में कहें तो, कार्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, और यदि यह उपरोक्त शब्दों के दायरे में आता है, तो धारा 197 का संरक्षण संबंधित लोक सेवक तक बढ़ाना होगा। इसलिए, यह निर्णय बताता है कि संहिता की धारा 197(1) की व्याख्या करते समय

और मामले के तथ्यों पर इसके अनुप्रयोग के दौरान न्यायालय को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पर मंत्री के रूप में कार्य करते हुए सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। आपराधिक साजिश का आरोप यह है कि उन्होंने बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और केरल बिजली बोर्ड नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों के तहत "केरल सरकार की सहमति के बिना" कर्नाटक राज्य में एक उद्योग को बिजली बेची, जो एक अवैध कार्य है। आरोप यह है कि कथित साजिश के अनुसरण में उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अवैध रूप से बैंगलोर (कर्नाटक) में निजी उद्योग को कुछ इकाइयाँ बेचीं, जिससे निजी उद्योग को 19,58,630.40 रुपये या उससे अधिक का लाभ हुआ और , इसलिए, स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप यह है कि बिजली मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने केरल सरकार की सहमति के बिना कर्नाटक में एक निजी उद्योग को बिजली की कुछ इकाइयों की आपूर्ति की। जाहिर है, उन्होंने एक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसा किया। आरोप यह है कि यह एक गैरकानूनी कार्य था क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले केरल सरकार की सहमति नहीं ली गई थी और आपूर्ति प्रभावित हुई। इस कारण से, यह कहा जाता है कि उसने एक अवैध कार्य किया था और इसलिए वह आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी था। इसलिए, आरोप से यह स्पष्ट है कि कथित कृत्य एक मंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्य से सीधे और उचित रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए, अधिनियम की धारा 197(1) के संरक्षण को आकर्षित करेगा।"

अंततः पी के प्रधान बनाम सिक्किम राज्य (2001) 6 एसएससी 704 पर भरोसा किया गया, हमारा ध्यान निम्न लिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया।

"5. धारा 197 की उपधारा (1) में शामिल विधायी आदेश एक अदालत को उस मामले में संबंधित सरकार की पिछली मंजूरी के अलावा किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है, जहां शिकायत किये गए कार्य कथित तौर पर लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या अपने आधिकारिक कर्तव्य का तात्पर्यिक निर्वहन कर रहा है द्वारा की गई हैं, और ऐसे लोक सेवक को सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से पद से हटाया नहीं जा सकता, वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह क़ानून द्वारा संज्ञान लेने पर लगाया गया निषेध है। संहिता की धारा 197 में आने वाले प्रासंगिक शब्दों के दायरे और अर्थ का पता लगाने के लिए निर्णीत मामलों में अलग-अलग परीक्षण निर्धारित किए गए हैं "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए कथित तौर पर उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध।" जिस अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, उसका आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से कुछ लेना-देना होना चाहिए, या किसी तरह से संबंधित होना चाहिए। धारा 197 के तहत मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं उठता, जब तक कि जिस कृत्य की शिकायत की गई है वह अपराध न हो; निर्धारण का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या यह आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कारित किया था। कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही कर्तव्य निर्वहन के लि कार्य सख्ती से आवश्यक सीमा से अधिक हो क्योंकि यह प्रश्न बाद के चरण में ही उठेगा जब विचारण गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ेगा। अदालत

को यह पता लगाना है कि क्या कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि कोई यह उचित रूप से मान सकता है कि यह आरोपी द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था, हालाँकि, संभवतः स्थिति की ज़रूरतों और अपेक्षाओं से अधिक।

15. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट होगा कि संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि शिकायत किए गए कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच उचित संबंध है। कोई सरकारी कार्य सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में भी किया जा सकता है और उसकी उपेक्षा में भी। संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा का आश्रय लेने के लिए, आरोपी के शिकायत किए गए कृत्य ऐसे होने चाहिए कि उन्हें आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से अलग नहीं किया जा सके, लेकिन यदि उनके और उन कर्तव्यों के निर्वहन के बीच कोई उचित संबंध नहीं था, आधिकारिक स्थिति केवल कृत्यों के लिए अवसर प्रदान करती है, तो किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा रखा गया मामला विफल हो जाता है या बचाव पक्ष यह स्थापित कर देता है कि किया जाने वाला कार्य कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है, तो कार्यवाही को बंद करना होगा। यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी का सवाल संज्ञान के बाद किसी भी समय उठाया जा सकता है, संज्ञान या आरोप तय होने के तुरंत बाद या मुकदमे के समापन के समय और दोषसिद्धि के बाद भी। लेकिन ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां बचाव पक्ष को यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना प्रश्न का प्रभावी ढंग से निर्णय करना संभव नहीं हो सकता है कि उसने जो किया वह आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अभियुक्त का यह दावा

कि उसने जो कार्य किया वह अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किया था, उचित था और न तो दिखावा था और न ही काल्पनिक था, बचाव पक्ष को इसे स्थापित करने का अवसर देकर विचारण के दौरान जांच की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, मंजूरी के सवाल को मुख्य निर्णय में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, जो विचारण के समापन पर सुनाया जा सकता है।"

कुल मिलाकर, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, यह तर्क दिया गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि नीरज कुमार को 24.06.1999 से हिरासत में लिया गया था, अपीलकर्ताओं द्वारा उसकी हिरासत अपीलकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में "कार्य करते समय या कार्य करने के उद्देश्य से" थी। और इस प्रकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपूरथला, 'संहिता' की धारा 197 के तहत मंजूरी के बिना, संज्ञान नहीं ले सकते थे।

11. श्री वरिंदर एस राणा, विद्वान अधिवक्ता जो प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित हुए, ने अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों का गंभीरता से विरोध किया। प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया :

"जहां तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का सवाल है, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्क संभवतः 28.06.1999 से हिरासत की अवधि के लिए लागू हो सकते हैं जब नीरज कुमार को प्राथमिकी संख्या 30 दिनांक 03.03.1999. को गिरफ्तार दिखाया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता 24.06.1999 से 28.06.1999 तक नीरज कुमार की अवैध हिरासत और यातना के लिए संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं, जब उनकी गिरफ्तारी प्राथमिकी संख्या 30 दिनांक 03.03.1999 को

दिखाई गई थी। अवैध हिरासत और यातना की उक्त अवधि का याचिकाकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन या कथित निर्वहन के साथ कोई संबंध नहीं है। नतीजतन, आक्षेपित आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि उपरोक्त अवधि के दौरान नीरज कुमार की अवैध हिरासत और यातना के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।"

उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी हमारा ध्यान ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य, (2012) 12 एससीसी 72 की ओर आकर्षित किया, जिसमे इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

32. कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या कार्य करना चाह रहा था, इसकी सच्ची परीक्षा यह होगी कि क्या जिस कार्य की शिकायत की गई है वह सीधे तौर पर उसके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा था या यह उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था या यह उसके कार्यालय से इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था कि उससे अविभाज्य हो (के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 266)। संहिता की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा की कुछ सीमाएँ हैं और यह केवल तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उचित रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और आपत्तिजनक कार्य करने के लिए केवल एक आवरण न हो। यदि अपने आधिकारिक कर्तव्य को निभाते समय, उसने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक उचित संबंध है, लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए अधिकता पर्याप्त आधार नहीं होगी (उड़ीसा

राज्य बनाम गणेश चंद्र जू (2004) 8 एससीसी 40)।) यदि उपरोक्त परीक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं, पुलिस को संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है वे उनके कार्यालय से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि उससे अविभाज्य हैं। हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि संहिता की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा का उपयोग पुलिस कर्मियों द्वारा इस मामले में मृतक को बेरहमी से मारने के लिए एक आवरण के रूप में किया जाता है।"

इसके बाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करने के लिए, विशेष रूप से गैरकानूनी हिरासत के संदर्भ में, उषारानी बनाम पुलिस आयुक्त (2015) 2 केएआरएलजे 511 (कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय) पर भरोसा किया गया जिसमें निम्नानुसार टिप्पणी की गई :

"10. हुड फिलिप्स और जैक्सन द्वारा संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में, यह इस प्रकार कहा गया है:

"हिरासत के किसी भी रूप की वैधता को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के एक आवेदन द्वारा सामान्य कानून में चुनौती दी जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट थी, यानी, राजा द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अपने कार्यों को ठीक से करने के लिए बाध्य करने के लिए जारी की गई थी. स्वतंत्रता के लिए आवेदक के दावे के निर्धारण के लिए त्वरित न्यायिक उपचार प्रदान करने के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण के व्यावहारिक महत्व पर अक्सर न्यायाधीशों और लेखकों द्वारा जोर दिया गया है। बहरहाल, उपाय की प्रभावशीलता कई मामलों में वैधानिक शक्ति की व्यापकता पर निर्भर करती है जिसके तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण कार्य कर सकता है और व्यापक

वैधानिक प्रावधान पर निर्भरता में किए गए निर्णय की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालयों की इच्छा पर निर्भर करता है। यह सुझाव दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के "सीधे उपचार" की आवश्यकता कम हो गई है क्योंकि न्यायिक समीक्षा और अधिक लचीले क्षेत्राधिकार में विकसित हो गई है। रिट का प्रक्रियात्मक सुधार उचित हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और न्यायिक समीक्षा के तहत उपचारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को नजरअंदाज न किया जाए। बाद वाला विवेकाधीन हैं और अदालत व्यावहारिक आधार पर राहत देने से इनकार कर सकती है; बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अधिकार रिट है, जिसे न्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है.

11. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्राचीन विशेषाधिकार रिट अपना नाम दो अनिवार्य शब्दों "हैबियस " और "कॉर्पस" से लेती है. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' का शाब्दिक अर्थ है 'सशरीर'। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, इन रिटों का सामान्य उद्देश्य किसी न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष व्यक्ति की पेशी प्राप्त करना था। यह गैरकानूनी या अनुचित हिरासत से तत्काल रिहाई की प्रभावी राहत प्रदान करके विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रक्रिया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में। यह एक ऐसे संप्रभु और उत्कृष्ट अधिकार की रिट है कि सत्ता या स्थान का कोई भी विशेषाधिकार इसके विरुद्ध नहीं टिक सकता। यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के भी मनमाने कृत्यों के विरुद्ध विषय के लिए एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा है, सभी संवैधानिक न्यायविदों के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है. रिट एक विशेषाधिकार है जिसे अपनी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इंग्लैंड में, रिट देने का क्षेत्राधिकार सामान्य कानून में मौजूद था, लेकिन क़ानून द्वारा इसे मान्यता दी

गई और बढ़ाया गया है। इंग्लैंड में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट अधिकार के रूप में है और न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने का कोई विवेक नहीं है। "उत्प्रेषण या परमादेश के विपरीत, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकार के रूप में है।" भारत में, यह विशेषाधिकार रिट है जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसलिए, यह इस देश के नागरिक के लिए उपलब्ध एक असाधारण उपचार है, जिसे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत लागू कर सकता है।"

12. जब किसी हस्तगत प्रकृति के प्रतिपादना का सामना किया जाता है, तो पहला कार्य, जिसे न्यायालय शुरू करने के लिए बाध्य होता है, वह यह सुनिश्चित करना है कि क्या कथित अपराध, जिसको अभियुक्त पर आरोपित किया गया है, अभियुक्त द्वारा "अपने आधिकरिक कर्तव्य का कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते हुए" कारित किया गया था. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कथित कार्रवाई 24.06.1999 से 28.06.1999 तक नीरज कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत पर आधारित है (इससे पहले, उसे 28.06.1999 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था)।

13. जहां तक पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत की शक्ति का सवाल है/'संहिता' की धारा 36 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो बताती है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के सभी पुलिस अधिकारियों को समान शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है (पूरे स्थानीय क्षेत्र में, जहां उन्हें नियुक्त किया गया है), जिसका प्रयोग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया

जा सकता है। 'संहिता' की धारा 49 बताती है कि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते समय किस प्रकार कार्य करना है। 'संहिता' की धारा 49, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान करती है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति, उसके भागने को रोकने के लिए, आवश्यक से अधिक संयम के अधीन नहीं है। 'संहिता' की धारा 50 में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है (जैसा कि वर्तमान मामले में कथित स्थिति है), हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपराध का पूरा विवरण तुरंत बताना अनिवार्य है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है साथ ही, ऐसी गिरफ़्तारी का आधार भी। धारा 50 ए गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को बाध्य करती है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्तों/रिश्तेदारों को (गिरफ्तार व्यक्ति से विवरण प्राप्त करने पर) उसकी हिरासत के बारे में तुरंत सूचित करे। और गिरफ्तारी की एक प्रविष्टि, और बंदी द्वारा नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी की जानकारी का संचार, उक्त उद्देश्य के लिए पुलिस स्टेशन में बनाए गए एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना है। 'संहिता' की धारा 50ए यह भी आदेश देती है कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाएगा, वह खुद को संतुष्ट करेगा कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा निर्वहन किए जाने वाले दायित्वों का पालन किया गया है।

14. 'संहिता' के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, इस तथ्य के बारे में कोई गंभीर संदेह नहीं हो सकता है, कि सुरिंदरजीत सिंह मंड और पीएस परमार, प्रासंगिक समय पर (24.06.199 से 28.06.1999 तक) पुलिस उपाधीक्षक के पद पर थे। दोनों अपीलकर्ता "...एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी थे..."। इसलिए दोनों अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक समय पर (24.06.1999 से 28.06.1999 तक) नीरज कुमार को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त था। संदर्भाधीन अवधि (24.06.1999 से 28.06.1999 तक) के लिए धारा 49, 50 और

50ए में आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नीरज कुमार को 28.06.1999 को ही गिरफ्तार किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाई गई स्थिति यह थी कि नीरज कुमार 24.06.1999 से 28.06.1999 की अवधि के लिए हिरासत में नहीं थे।

15. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित 'संहिता' के प्रावधानों से उभरने वाली कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क था कि 'संहिता' की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता के लिए, इसे और स्थापित करने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ताओं ने 'संहिता' के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए तरीके से कार्य किया था, उस अवधि के दौरान जब नीरज कुमार को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया था (24.06.1999 से 28.06.1999 तक), यानी, 28.06.1999 को उसकी स्वीकृत औपचारिक गिरफ्तारी से पहले। और केवल अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो धारा 197 के तहत मंजूरी मांगने की आवश्यकता उत्पन्न होती, क्योंकि उस स्थिति में, कथित रूप से किया गया अपराध "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का इरादा रखते हुए" किया गया माना जाएगा। वर्तमान मामले में, नीरज कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत 24.06.1999 से 28.06.1999 तक अस्वीकृत किया जाता है। 24.06.1999 को नीरज कुमार की कथित गिरफ्तारी पर 'संहिता' के तहत निर्धारित औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया, क्योंकि अपीलकर्ताओं के अनुसार, नीरज कुमार को उस तारीख को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि 28.06.1999 से पहले कोई भी गिरफ्तारी या हिरासत, यदि सच है, तो स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी और हिरासत की अनिवार्य शर्तों का पालन किए बिना, प्रावधानों (ऊपर संदर्भित) के तहत विचार किया गया था। और इसलिए, "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने के उद्देश्य" के दायरे में नहीं आएंगे।

16. पूर्वगामी पैराग्राफों में प्रस्तुत तर्कों का समर्थन करने के लिए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने पीपी उन्नीकृष्णन बनाम पुट्टियोट्टिल अलीकुट्टी (2000) 8 एससीसी 131, पर भरोसा जताया, और उसमे की गई टिप्पणियों के ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

> "21. यदि कानून और व्यवस्था के निर्वहन में कोई पुलिस अधिकारी अपने बचाव में या दूसरों के बचाव में अनियंत्रित व्यक्तियों के खिलाफ बल का प्रयोग करता है और ऐसे अधिकार का उल्लंघन करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन ऐसा अपराध संहिता की धारा 197 के साथ-साथ केपी अधिनियम की धारा 64(3) के दायरे में आ सकता है। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी लॉक-अप के अंदर किसी कैदी पर हमला करता है तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसा कृत्य उसके अधिकार के निर्वहन या उसके कर्तव्य के निष्पादन से जुड़ा है जब तक कि वह यह स्थापित न कर दे कि उसने ऐसा कृत्य अपने बचाव या दूसरों या किसी संपत्ति की रक्षा में किया है. इसी तरह, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की मंजूरी या अदालत के आदेश के बिना गलत तरीके से 24 घंटे की अवधि से अधिक समय तक लॉक-अप में कैद रखता है, तो यह एक अपराध होगा जिसके लिए वह सामान्य प्रक्रिया में किसी भी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है, न ही वह यह दावा कर सकता है कि ऐसा कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए किया गया था। एक पुलिसकर्मी द्वारा किसी व्यक्ति को बिना अधिकार के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखना न केवल अपने कर्तव्य का दुरुपयोग है, बल्कि उसका कृत्य उसके कर्तव्य या अधिकार के दायरे से बाहर होगा।'

पुलिस कर्मियों (ऊपर संदर्भित) के हाथों व्यक्तियों की गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित 'संहिता' के प्रावधानों के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि 28.06.1999 से 30.06.1999 तक नीरज कुमार की गिरफ्तारी निर्विवाद रूप से "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने के उद्देश्य" के दायरे में आएगी (नीरज कुमार को गिरफ्तार करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की)। हालाँकि, यह दावा किया गया था कि यदि 24.06.1999 से 28.06.1999 तक (28.06.1999 को औपचारिक रूप से हिरासत में लिए जाने से पहले) नीरज कुमार की गिरफ्तारी तथ्यात्मक रूप से सही पाई जाती है, नीरज कुमार की इस तरह की गिरफ्तारी को अपीलकर्ताओं- सुरिंदरजीत सिंह मंड और पीएस परमार द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए कथित तौर पर किया गया होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह तर्क किया गया कि 24.06.1999 से 28.06.1999 तक नीरज कुमार की हिरासत के संबंध में, किसी भी कथित आपराधिक मामले को संबंधित न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले धारा 197 के तहत संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क पर गहनता से विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि पीपी उन्नीकृष्णन मामले (उक्त) में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्पष्ट और सशक्त है। यह किसी भी विकल्प को चुनने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। यह स्पष्ट है कि, यहां ऊपर उल्लिखित 'संहिता' के प्रावधानों के अनुसार, नीरज कुमार की आधिकारिक गिरफ्तारी 28.06.1999 से 30.06.1999 की अवधि के दौरान बढ़ेगी। हिरासत की उपरोक्त अवधि को वैध रूप से "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के उद्देश्य से" के रूप में माना जा सकता है। अपीलकर्ताओं द्वारा व्यक्त तथ्यात्मक स्थिति यह है

कि नीरज कुमार को 24.06.1999 से 28.06.1999 की अवधि के लिए हिरासत में नहीं लिया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान उनकी हिरासत, अगर सच है, तो हमारे विचार में निश्चित रूप से अभियुक्तों के कार्य "जबकि वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के आशय से हो. से सामने नहीं आएगा। यदि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से यह पता चलता है कि नीरज कुमार को वास्तव में 24.06.1999 से 28.06.1999 की अवधि के दौरान हिरासत में लिया गया था, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त हिरासत अभियुक्तों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कार्य करते समय या कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। इससे भी अधिक, क्योंकि यह अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है, कि उन्होंने 24.06.1999 से 28.06.1999 की अवधि के दौरान नीरज कुमार को जेल में रखा था। यदि उन्होंने उपरोक्त अवधि के दौरान उसे हिरासत में नहीं लिया था, यह स्थिति मानने के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है कि उपरोक्त अवधि के दौरान नीरज कुमार की हिरासत, उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने के उद्देश्य के तौर पर थी। इसलिए, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, पीपी उन्नीकृष्णन मामले (उक्त) में, इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति के आधार पर, हमारा मानना है कि 24.06.1999 से 28.06.1999 तक की अवधि के लिए नीरज कुमार की हिरासत के संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जो नीरज कुमार की कथित गिरफ्तारी के संदर्भ में संज्ञान लेता है। इसलिए, हम उपरोक्त आशय के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन करते हैं।

18. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का यह भी तर्क था कि 'संहिता' की धारा 197 के तहत लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए कृत्यों के कारण अभियोजन से पहले मंजूरी देने की जो सुरक्षा प्रदान की गई है,

इसका उद्देश्य लोक सेवकों को निजी व्यक्तियों के हाथों अभियोजन के तुच्छ उत्पीड़न से बचाना है। इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की दलील थी कि 'संहिता' की धारा 197 का दायरा, 'संहिता' के अध्याय XIV के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने तक सीमित होना चाहिए, जिसमें ऐसी शुरुआत धारा 190 के तहत निर्धारित की जाती है (किसी शिकायत की प्राप्ति पर, जिसमें तथ्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया था)। उपरोक्त सभी स्थितियों में, एक मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे अपराध का संज्ञान लेना इस शर्त के अधीन खुला है कि वह उक्त मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकार क्षमता के अंतर्गत आता है। हालाँकि, संबंधित सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, मजिस्ट्रेट एक लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और यदि यह एक मजिस्ट्रेट की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसे सत्र न्यायालय को सौंपा जा सकता है, जो इसका संज्ञान ले सकता है, जैसा कि 'संहिता' की धारा 193 द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद, जिस न्यायालय को मामला सौंपा गया है, वह 'संहिता' की धारा 197 के तहत संबंधित सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, एक लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मंजूरी के उपरोक्त दायरे पर जोर देते हुए, यह बताया गया कि 'संहिता' की धारा 197 'संहिता' के अध्याय XIV का एक हिस्सा है, इसकी प्रयोज्यता अकेले अध्याय-XIV के तहत प्रावधानों तक विस्तारित होगी। यह तर्क दिया गया था कि 'संहिता' की धारा 319 अध्याय XXIV में निहित है, जिस पर धारा 197 का कोई असर नहीं हो सकता है।

19. पूर्वगामी पैराग्राफ में देखे गए तर्कों की निरंतरता में, उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 'संहिता' की धारा 197 के तहत विचार किया, और संज्ञान लेने में न्यायालय की कार्रवाई, शिकायतों के आधार पर शुरू की गई कार्रवाइयों से संबंधित है, जो किसी अपराध के घटित होने का

खुलासा करती है, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी प्राप्त होने पर कि ऐसा अपराध किया गया है। यह दावा किया गया था कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की उपरोक्त कार्रवाई कथित "तथ्यों" पर आधारित है, न कि न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए "सबूतों" पर। उपरोक्त अंतर 'संहिता' की धारा 190 का हवाला देकर निकाला गया था, जो किसी आरोपी के खिलाफ कथित तथ्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू करने पर विचार करता है, जबकि 'संहिता' की धारा 319 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई तभी शुरू की जाती है, जब मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति किसी अपराध में शामिल था। 'संहिता' की धारा 319 का संदर्भ देते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि 'संहिता' की धारा 319 के तहत लिया गया संज्ञान न्यायालय द्वारा ही लिया गया था, और इसलिए, यह "साक्ष्य" पर आधारित होने के साथ-साथ न्यायालय की संतुष्टि पर भी आधारित है कि ऐसे व्यक्ति पर "अन्य अभियुक्तों" के साथ मिलकर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, यह अनुचित लग रहा था कि 'संहिता' की धारा 197 के तहत निर्धारित मंजूरी की अभी भी आवश्यकता होनी चाहिए। यह इंगित किया गया था, कि 'संहिता' की धारा 197 के तहत विचार की गई सुरक्षा एक पूर्व-आवश्यकता नहीं थी, जब संज्ञान न्यायालय द्वारा "साक्ष्य" के मूल्यांकन पर आधारित था। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जब एक न्यायालय ने स्वयं निर्धारित किया है कि उसी न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों के आधार पर संज्ञान लिया जाना आवश्यक है, तो यह संबंधित न्यायालय के अधिकार को कमजोर कर देगा, यदि इसका न्यायिक निर्धारण, 'संहिता' की धारा 197 के तहत अनुध्यात अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन माना जाता था। ऊपर देखी गई दलीलों के आधार पर, यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का जोरदार

तर्क था कि धारा 197 का आदेश उन मामलों तक विस्तारित नहीं होगा जहां 'संहिता' की धारा 319 के तहत संज्ञान लिया गया था।

20. पहले तर्क से निपटते समय, हमने पहले ही अपने निष्कर्ष दर्ज कर लिए हैं, जो विचाराधीन मामले के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन, उत्तरदाताओं की ओर से दूसरे तर्क के रूप में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रस्ताव प्रचारित किया गया है (जिसे हमने पिछले पैराग्राफ में दर्ज किया है)। चूँकि यह इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से सामने आता है, इसलिए हम उस पर अपना दृढ़ संकल्प प्रस्तुत करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। आगामी अनुच्छेदों में, हम दूसरे तर्क से निपटेंगे।

21. जहां तक उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए दूसरे तर्क का सवाल है, हमारा विचार है कि प्रस्तावित प्रस्ताव के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त मिसाल मौजूद है। पहले उदाहरण में दिलावर सिंह बनाम परविंदर सिंह उर्फ इकबाल सिंह, (2005) 12 एससीसी 709 का संदर्भ दिया जा सकता है। उपरोक्त उद्धृत निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियाँ वर्तमान मुद्दे के लिए प्रासंगिक हैं:

> "2. वर्तमान अपीलों को उत्पन्न करने वाले बुनियादी तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्नी की शिकायत पर परविंदर सिंह उर्फ इकबाल सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406/498-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. 27.1.2000 को परविंदर सिंह उर्फ इकबाल सिंह ने एसएसपी, बरनाला को शिकायत दी कि 23.1.2000 को जसबीर सिंह, एएसआई और एक होम गार्ड स्कूटर पर उनके घर आए और उन्हें जबरन पुलिस स्टेशन बमाला में ले गए। उसे पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और थर्ड-डिग्री तरीकों (शारीरिक क्रूरता) का इस्तेमाल किया गया। उनके कुछ रिश्तेदार, अर्थात् जमैल सिंह, सुखदेव सिंह, साधु सिंह ग्रेवाल और सुखदेव सिंह विर्क पुलिस स्टेशन आए और पुलिस

कर्मियों से अनुरोध किया कि वे उसे न मारें और न ही प्रताड़ित करें। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि जसबीर सिंह, ए.एस.आई. ने उनसे कहा कि वे एस.एच.ओ. दिलावर सिंह से बात करें जो वहां एक कुर्सी पर बैठा था. दिलावर सिंह ने परविंदर सिंह को रिहा करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की। उसके रिश्तेदार फिर रकम लेकर आए, जिसमें से 15,000 रुपये दिलावर सिंह को देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसा एएसआई जसबीर सिंह को दिया जा सकता है। फिर 15,000/- रुपये की राशि एएसआई जसबीर सिंह को दी गई, जो उसने अपने कोट की जेब में रख लिया। परविन्दर सिंह का 28/1/2000 को मेडिकल परीक्षण कराया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद केवल एएसआई जसबीर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. दिलावर सिंह, एसएचओ के खिलाफ एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई क्योंकि जांच अधिकारी की राय में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि एएसआई जसबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई थी। शिकायतकर्ता परविंदर सिंह का बयान दर्ज होने के बाद, उन्होंने मामले में सह-अभियुक्त के रूप में दिलावर सिंह, SHO को तलब करने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया। पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 7.1.2002 द्वारा आवेदन खारिज कर दिया। परविंदर सिंह ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.7.2002 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दे दी है और दिलावर सिंह को

तलब करने और कानून के अनुसार मुकदमा चलाने का निर्देश जारी किया गया है।

4. हमारी राय में, विद्वान वकील अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क सुस्थापित है। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (I), जो विवाद के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"19. अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक.-

(1) कोई भी अदालत धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जो कथित तौर पर किसी लोक सेवक द्वारा किया गया हो, पूर्व मंजूरी के अलावा, -

(ए) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत है और उस सरकार की केंद्रीय सरकार की मंजूरी के अलावा उसके कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है;

(बी) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो किसी राज्य के मामलों के संबंध में कार्यरत है और उस सरकार की राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है;

(सी) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी।"

यह धारा, धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की अदालत की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, इस उपधारा के खंड (ए) से (सी) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी की पिछली

मंजूरी को छोड़कर। यदि उपधारा को समग्र रूप से पढ़ा जाए, यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि अभियोजन की मंजूरी एक विशिष्ट आरोपी के संबंध में दी जानी है और मंजूरी दिए जाने के बाद ही न्यायालय को धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की क्षमता मिलती है जो ऐसे लोक सेवक द्वारा कारित किया गया है। धारा को प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से पढ़ना संभव नहीं है कि यदि एक आरोपी के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई है, तो कोई अन्य लोक सेवक जिसके अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है, उसे भी अभियोजन का सामना करने के लिए भी बुलाया जा सकता है।

5. राज्य बनाम राज कुमार जैन में, (1998) 6 एससीसी 551 में, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6(1) के दायरे की जांच कर रहा था, जो लगभग अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के समान है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6(1) के प्रावधानों को उद्धृत करने के बाद, इसे रिपोर्ट के पैरा 5 में निम्नानुसार रखा गया था: {एससीसी पृ. 552-53)

"5. उपरोक्त धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता है। उपरोक्त धारा को अधिनियमित करते समय, विधायिका ने लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में उचित सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सोचा ताकि वे कष्टप्रद और अनावश्यक अभियोजनों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन कर सकें।"

6. जसवन्त सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 124 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(1)(डी) के तहत अपराध के

लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 5(एल)(ए) के तहत उनके अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। यह माना गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(ए) के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उक्त अपराध के संबंध में कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन आरोपी पर उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान के तहत अभियोजन के लिए वैध मंजूरी थी।

7. 29.9.2005 को इस पीठ द्वारा निर्णीत गोवा राज्य बनाम बाबू थॉमस, (2005) 8 एससीसी 130 में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस तारीख को विशेष न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान लिया, उस तारीख पर वैध मंजूरी के अभाव में, संज्ञान लेना अधिकार क्षेत्र के बिना और पूरी तरह से अमान्य था। यह, कानून की सुस्थापित स्थिति होने के नाते, अपीलकर्ता को तलब करने और जसबीर सिंह, एएसआई के साथ उसके खिलाफ कार्यवाही करने का उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से कानून में गलत है।

उपरोक्त मुद्दे की जांच इस न्यायालय द्वारा पॉल वर्गीस बनाम केरल राज्य, (2007) 14 एससीसी 783 में भी की गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"2. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को है, जिसमें वर्तमान अपील में प्रतिवादी 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण की अनुमति दी गई है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता था। उन्होंने जांच आयुक्त एवं विशेष न्यायाधीश, त्रिचूर द्वारा पारित आदेश

की सत्यता पर सवाल उठाया था, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 319 के संदर्भ में आरोपी के रूप में उसे पक्षकार बनाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। उक्त आदेश के द्वारा ट्रायल कोर्ट ने माना था कि संहिता की धारा 319 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 19 के प्रावधानों को खत्म कर देती है, और पूर्व प्रावधान के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें धारा 319 की उप-धारा (4) में ही निर्धारित की गई हैं। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि दिलावर सिंह बनाम परविंदर सिंह उर्फ इकबाल सिंह और अन्य (2005 (12) एससीसी 709) मामले में इस न्यायालय ने जो कहा है, उसके मद्देनजर यह दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है। तदनुसार, आदेश को रद्द कर दिया गया।

4. जैसा कि दिलावर सिंह के मामले (उक्त) में कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है, विचारण न्यायलय का यह मानना उचित नहीं था कि संहिता की धारा 319 को अधिनियम की धारा 19 पर प्राथमिकता/प्रधानता मिलनी चाहिए, और यह मामला समाप्त होता है..."

सबसे अंत में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, (2012) 3 एससीसी 64 में इस न्यायालय के हालिया फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। संदर्भाधीन मुद्दे के लिए, उपरोक्त निर्णय में दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:

"74. उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमें करना चाहिए, अगर हम पी.सी. अधिनियम की धारा 19 को देखें जो एक अदालत को धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का संज्ञान लेने से रोकती है, जब तक कि, जैसा भी मामला हो, केंद्र या राज्य

सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, तब तक यह वस्तुतः निजी नागरिकों और अभियोजकों पर भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ अदालत जाने से रोक लगाती है। ये संरक्षण अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लोक सेवकों को उक्त सुरक्षा का आनंद लेने वाले व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग के रूप में माना जाता है ताकि वे बिना किसी डर और पक्षपात के और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की धमकियों के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हालाँकि, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ उक्त सुरक्षा, जिसे जनहित में बढ़ाया गया था, भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा के लिए ढाल नहीं बन सकती है। अनुच्छेद 14 के समानता प्रावधान के अपवाद होने के कारण ये प्रावधान सुरक्षात्मक भेदभाव के प्रावधानों के अनुरूप हैं और इन संरक्षणों को बहुत बारीकी से समझा जाना चाहिए। मंजूरी से संबंधित इन प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में वृद्धि के विपरीत ईमानदारी और न्याय और सुशासन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

75. इसलिए, प्रत्येक मामले में जहां पीसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के संबंध में अभियोजन की मंजूरी के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी का यह परम कर्तव्य है कि वह स्थिति पर तुरंत अपना दिमाग लगाए और किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित हुए बिना मुद्दे का निर्णय करे। ऐसा करने में, प्राधिकारी को कानून के नियम और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए। ऐसी मंजूरी देने या अस्वीकार करने के सवाल पर विचार करते समय, प्राधिकरण केवल कानून के प्रति जवाबदेह है। इसलिए, ऐसी स्थिति में उचित शीघ्रता के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। मंजूरी प्रस्ताव देने में देरी एक बहुत ही वैध सामाजिक उद्देश्य को विफल कर देती है, अर्थात्, अपराधी को सजा

दिलाने की आवश्यकता के साथ त्वरित विचारण का उद्देश्य। इसलिए, इस मामले में, मंजूरी देने या मंजूरी देने से इनकार करते समय मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का अधिकार एक कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है।"

22. इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, यहां ऊपर उल्लिखित निर्णयों में से, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, 'संहिता' की धारा 197 के तहत और/या एक विशेष क़ानून के तहत अनिवार्य मंजूरी (जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्धारित है) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय जो किसी अपराध का संज्ञान लेता है (चाहे भारतीय दंड संहिता के तहत, या संबंधित विशेष वैधानिक अधिनियम के तहत), एक पूर्व-आवश्यकता होगी। मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया 'संहिता' के प्रावधानों और/या विशेष अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से नियंत्रित होगी। 'संहिता' की धारा 197 में शामिल शब्द हैं, "...कोई भी अदालत पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी...। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रावधान है, "कोई भी अदालत पिछली मंजूरी के अलावा संज्ञान नहीं लेगी..."। आदेश स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय बिना मंजूरी के संज्ञान नहीं लेगा। इसे और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, कोई न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता। इस प्रकार देखा जाए तो, हमें उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए दूसरे तर्क में कोई गुण नहीं मिलता है, जहां 'संहिता' की धारा 319 के तहत संज्ञान लिया जाता है, वहां 'संहिता' की धारा 197 (या संबंधित विशेष अधिनियम के तहत) के तहत मंजूरी अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता नहीं है।

23. प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के अनुसार, ऊपर निष्कर्षित स्थिति से यह आभास होगा कि कि 'संहिता' की धारा 319 के तहत

न्यायालय द्वारा किया गया निर्धारण, धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अधीन है। नहीं, बिलकुल नहीं। धारा 197 के तहत मंजूरी दिए जाने पर अभियुक्त द्वारा न्यायिक समीक्षा का सहारा लेकर चुनौती दी जा सकती है। इसी तरह, मजूरी को ख़ारिज करने वाला आदेश को शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष द्वारा इसी तरह चुनौती दी जा सकती है।

24. यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, और पैराग्राफ 17 में हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं है और यह ख़ारिज किये जाने योग्य है. तदनुसार आदेश दिया गया।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।